

उदारवादी युग का आन्दोलन एवं जनपद-जालौन की भूमिका

डॉ० रणविजय सिंह,

प्रधानाचार्य,

राजकीय इटर कालेज,

लखैयाकला, नानपारा, बहराइच-उ०प्र०

सन् 1885-1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एवं कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा। इस काल में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले नेता ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे। जिन्होंने 20 साल तक कांग्रेस की बागडोर संभाली। इनमें प्रमुख थे-सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानाडे, उमेशचन्द्र बनर्जी तथा पंडित मदनमोहन मालवीय आदि। उदारवादी एकदम क्रांति रूप में नहीं वरन् क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रधान श्रेय ब्रिटिश शासन को है और ब्रिटिश शासन ने भारत के सामाजिक जीवन को पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का स्पर्श देकर उसमें स्वतन्त्रता की भावना जाग्रत की है। अतः यह उचित है कि देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे सुधार लाने की चेष्टा की जाए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अंग्रेजी शासन भारत के हित में है तथा वे आशा रखते थे कि कालान्तर में अंग्रेज उन्हें अपनी परम्पराओं के अनुसार स्वशासन के योग्य बना देंगे। उस समय इनकी मांगों में अवज्ञा तथा चुनौती का स्वर न होकर आग्रह और प्रार्थना का स्वर होता था। कांग्रेस की प्रमुख मांगें थीं, जैसे- भारत सचिव की इण्डिया कौंसिल को समाप्त किया जाए, केन्द्र और प्रान्तों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान अवसर तथा सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाएं भारत में भी आयोजित की जाएं आदि तक ही सीमित थी।

उदारवादियों की प्रारम्भिक कार्य पद्धति

उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पूर्ण रूप से संवैधानिक और ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग की भावनाओं पर आधारित होती थी। ये लोग सरकार से किसी भी स्थिति में टकराव नहीं चाहते थे। वे प्रार्थना पत्रों, आवेदन-पत्रों, प्रतिनिधि-मंडल और स्मरण-पत्रों आदि द्वारा सरकार से अपनी न्याययुक्त मांगों को मानने का आग्रह करते थे।

उदारवादियों ने सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रशासनिक कदमों की आलोचना करते हुए प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को दूर करने की आवाज उठाई। इस संबंध में महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन प्रशासनिक सेवा की उच्चतर श्रेणी के पदों का भारतीयकरण के संबंध में था। उदारवादियों ने सरकारी एजेण्टों व पुलिस द्वारा जनसाधारण के साथ दुर्व्यवहार का विरोध किया। इनकी एक महत्वपूर्ण मांग यह थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए ताकि जनसाधारण के हित में कुछ सुरक्षात्मक कार्य हो सके। कांग्रेस के प्रारम्भिक उदारवादी नेताओं ने कुछ गिने चुने व्यक्तियों को मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की अपील की। कांग्रेस के प्रारम्भिक उदारवादी नेता धीरे-धीरे आग्रहों, आवेदनों और प्रार्थनाओं द्वारा क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। परंतु एक बात अवश्य थी कि वे मौलिक सांविधानिक परिवर्तनों

के लिए शुरू से ही प्रयास करने लगे थे। इनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही सरकार ने पुरानी व्यवस्था में सुधार करके नया 'भारतीय विधान परिषद विधेयक, 1892' पास किया। इसमें गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने, सदस्यों को बजट पर बोलने आदि अधिकारों की व्यवस्था थी, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार 'इंडियन कौंसिल एक्ट, 1892' द्वारा भारतीय परिषदों में कुछ सुधार किए गए।

इसके बाद से भारतीयों के प्रति अंग्रेजों ने अधिक कठोरता का रुख अपनाया शुरू कर दिया था। सन् 1894 में इंग्लैण्ड से भारत में आने वाले कपड़े पर आयात-कर घटा दिया गया। सन् 1895-97 के वर्षों में दक्षिण भारत में अकाल की स्थिति व्याप्त थी तथा सन् 1897 में यहां भूकम्प से बहुत अधिक नुकसान हुआ। पूना और आस-पास के क्षेत्रों में प्लेग की स्थिति व्याप्त रही। परंतु सरकार इन सभी स्थितियों को अनदेखा करते हुए उदासीन बनी रही।

लार्ड कर्जन के समय सन् 1899-1905 के बीच सरकार ने अनेक अन्याय पूर्ण कानून पास किए तथा ऐसे कार्य किए जिनसे लोगों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया। सन् 1905 के बंगाल विभाजन ने तो लोगों के बीच तूफान खड़ा कर दिया। यद्यपि उदारवादी शासन व्यवस्था में अधिक सुधार करवाने में असफल रहे तथापि उन्होंने अपनी नरम नीति के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को एक मजबूत आधार अवश्य प्रदान किया और अनेक उपयोगी कार्य करने में भी सफलता प्राप्त की। कुल मिलाकर उदारवादी नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उन्होंने देशवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उदारवादी नीतियों में परिवर्तन करके बाद में कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज्य तथा स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया।

उदारवादी युग के प्रमुख नेता

दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के विख्यात वयोवृद्ध नेता थे। उनकी गणना महान देशभक्तों में की जाती है। कांग्रेस की स्थापना से अपनी मृत्यु तक वे इस संस्था से संबद्ध रहे। सन् 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष श्री गोखले को भेजे गए सन्देश में उन्होंने कहा था – 'भारत के दुःखों और बुराइयों का एक मात्र उपचार है स्वशासन है।'⁽¹⁾ सन् 1906 ई० में कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने लोकसेवाओं में भारतीयों की अधिक नियुक्ति, विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व और भारत व ब्रिटेन के बीच उचित आर्थिक संबंध स्थापित करने की माँग रखी। वे बाद में भारत में स्वशासन की स्थापना को भी अपना समर्थन देने लगे। उन्होंने स्पष्ट तौर से घोषित किया कि 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त करना ही कांग्रेस का लक्ष्य है।'

काँग्रेस के प्रतिष्ठित उदारवादी नेता सर फिरोजशाह मेहता थे। वे बंबई के प्रख्यात वकील थे। उनका राजनीतिक जीवन सन् 1870 ई० के आसपास आरंभ हुआ। सन् 1872 ई० में वे बंबई कॉरपोरेशन के सदस्य और सन् 1886 ई० में बंबई विधायिका के सदस्य बनाए गए। सन् 1890 ई० में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने। अंग्रेजी साम्राज्य को वे भी प्रगति का सूचक और भारत के लिए वे चाहते थे कि कांग्रेस वैधानिक मार्ग का ही अनुसरण करे। वे अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। वे अत्यन्त प्रभावशाली वक्ता थे और अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में करने की अद्भुत क्षमता रखते थे।

प्रारंभिक चरण में बंगाल ने जिन नेताओं को उत्पन्न किया उनमें सुरेन्द्र नाथ बनर्जी का स्थान अग्रगण्य है। सन् 1876 ई० में उन्होंने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी की। बंगाली पत्रिका को भी उन्होंने संपादन

किया। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। कांग्रेस की स्थापना में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे बंगाल प्रांतीय विधानसभा के सदस्य बने। उन्हें दो बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सर हेनरी काटन उनके सम्बन्ध में लिखते हैं— “अपनी वक्तृत्व शक्ति से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी मुल्तान से चिरगाँव तक कोई भी विद्रोह उत्पन्न कर सकते या दबा सकते हैं। भारत में उनकी स्थिति वही थी जो डेमोस्थनीज की यूनान में या सिसरो की इटली में।”⁽²⁾ सन् 1923 ई० में विधान सभा के चुनावों में वे स्वराज दल के सदस्य विधान चन्द्र राय से चुनाव हार गए। अंग्रेजी सरकार के पक्षधर होने के बावजूद कांग्रेसी नेताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत के रूप में विख्यात हैं।

उदारवादी नेताओं में गोखले का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका एवं सुधारक का कुशलता पूर्वक संपादन किया। सन् 1900 ई० में वे केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य बनाए गए। सन् 1905 ई० में बनारस कांग्रेस अधिवेशन के वे सभापति बने। चिंतामणि के अनुसार जो गोखले को अपना गुरु मानते थे— “गोखले बौद्धिक रूप से इतने ईमानदार थे कि वे पहले अपने आप से अच्छी तरह जिरह किये बिना कभी कोई राय प्रकट नहीं करते थे।”⁽³⁾ गोखले ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भूमिका का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि महात्मा गाँधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं इसके प्रारंभिक विकास में स्काटलैंड निवासी ए०ओ० ह्यूम का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कांग्रेस की स्थापना का श्रेय उन्हें ही प्रदान किया जाता है। वे एक उदारवादी थे। भारत और भारतीयों से उन्हें गहरी सहानुभूति थी। सन् 1885

ई० में कांग्रेस की स्थापना कर ही वे संतुष्ट नहीं हो गए, बल्कि जीवन भर वे कांग्रेस को अपना सहयोग देते रहे। उनके कार्यों से कांग्रेस की शक्ति अधिक बढ़ी।

उदारवादी युग में जनपद—जालौन

काँग्रेस की स्थापना के पूर्व भी भारत के शिक्षित, बुद्धिजीवी, जागरूक लोगों द्वारा समस्त भारतीयों को आपस में जोड़ने के प्रयास से एक राजनैतिक मंच संगठित करने की अकुलाहट इस वर्ग को लगातार जोर दे रही थी। परन्तु अंग्रेजों के कट्टरवादी शासन एवं दमन चक्र को भोग चुका भारतीय जनमानस इस अकुलाहट को मन में दबाये था। उनके इस अकुलाहट एवं बेचैनी को बाहर आने का श्रेय ए०ओ० ह्यूम की कविता की निम्नांकित पंक्तियों को जाता है, जिससे सकारात्मक रूप पाकर भारतीय जनमानस की दबी हुई आशाओं एवं अकुलताओं को पंख प्रदान कर दिये थे।

Sons of Ind, Why sit ye idle
wait ye for some deva's aid?
Buckle to, be up and doing
Nations by themselves are made'

(A.O.Hume)

उपरोक्त पंक्तियों से नई चेतना पाकर ए०ओ० ह्यूम के संरक्षण में दिसम्बर सन् 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के सन्दर्भ में जनपद—जालौन की जनता में कोई उत्साह का उल्लेख अभी तक अप्राप्य है। कांग्रेस को प्रारंभिक दौर में अंग्रेजी हुकूमत के पनाहगारों द्वारा संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिलता रहता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य, अंग्रेजी शासन की नजर में केवल भारतीय बुद्धिजीवियों के मिलन समारोह तक सीमित थे। परन्तु इन मिलन समारोहों ने भारतीय जनमानस में स्वतन्त्रता के वे तार संचालित कर दिये जिनकी धारण क्षमता समारोह—दर—समारोह

व्यापक होती गयी। जिसके फलस्वरूप काँग्रेस ने भारतीय जनों की स्वतन्त्रता की आंकाक्षाओं को अभिव्यक्त करने की मान्यता प्राप्त संस्था का रूप ग्रहण कर लिया।

तत्कालीन समय का उत्तर पश्चिमी प्रान्त व अवध, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, में विधानी परिषद की प्रथम बैठक इलाहाबाद के थार्नहिल मेमोरियल में सम्पन्न हुई, जिससे प्रान्त में सन् 1887 से प्रतिनिधि शासन की शुरुवात हुई। विद्यायी परिषद की बैठक द्वारा प्रान्त में क्षेत्रीय सीमा को निर्धारित कर प्रशासन का पुनर्गठन किया गया एवं पटवारियों को वेतन आदि प्रदान करने की व्यवस्था भी की गयी। इस परिषदीय बैठक में जनपदीय प्रतिनिधि का पूर्णता अभाव था परन्तु इलाहाबाद मण्डल के लिए पारित किये गये सभी कानून को लागू करने का प्रारम्भ जनपद जालौन में भी इसी प्रावधान के तहत पहली बार शुरुवात हुई।

सन् 1887 में देश में पड़े भीषण अकाल व सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेजी शासन द्वारा बम्बई से कानपुर को जोड़ने के लिए सन् 1889 में ग्रेट इंडियन पेनीसुला रेलवे की ओर से रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। यद्यपि यह लाइन कानपुर व बम्बई को जोड़ने के लिए बनाई गयी थी पर इस रेलवे लाइन के जनपद से गुजरने के कारण जनपदीय व्यापार व वाणिज्य को भी विकसित होने का अवसर प्रदान किया। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक व सन् 1900 ई० में पड़े भीषण अकाल के प्रकोप से बचने में इस लाइन ने काफी राहत दी। यद्यपि सन् 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में जनपद-जालौन क्रान्तिकारी गतिविधियों का केन्द्र रहा था परन्तु सन् 1857 के पश्चात भी जालौन में ठाकुर बरजोर सिंह द्वारा क्रान्ति की अलख जलाई रखी गयी। जिससे अंग्रेज प्रशासन ने जनपद में क्रान्ति का दमन काफी मशकत के बाद किया जा सका। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रान्ति

के पश्चात जनपद जालौन के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब सम्पूर्ण अवध क्षेत्र में सन् 1901 ई० में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गयी तब से जनपद में सरकारी गतिविधियाँ तेज हुईं। सन् 1902 ई० में उत्तरी पश्चिमी प्रान्त व अवध का नाम परिवर्तित कर संयुक्त प्रान्त आगरा एवं अवध कर दिया गया।⁽⁴⁾ जनपद में संयुक्त प्रान्त आगरा एवं अवध की प्रशासकीय व्यवस्था लागू कर दी गयी। लार्ड कर्जन के (सन् 1898-1905) के दमनकारी शासन, अन्यायपूर्ण, भेदभाव से भरपूर नीतियों के चलते समस्त भारतीय जनता त्रस्त तो थी ही साथ-ही-साथ सन् 1896-97 में पड़े भीषण अकाल व सूखा में सरकार की तरफ से राहत के कोई उपाय न किये जाने के कारण समस्त भारतीय जनमानस के साथ जनपदीय जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। जिसको अभिव्यक्त करने का मंच काँग्रेस के होने वाले अधिवेशनों में प्रदान किया।

सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रहे जनपद-जालौन में काँग्रेस के नीतियों को अपनाने वाले प्रथम जनपदीय उदारवादी श्री गोपाल दास शर्मा थे। जिन्होंने सन् 1892 में इलाहाबाद में हुए काँग्रेस के 8 वें अधिवेशन में एक स्वयं सेवक के रूप में जनपदीय भागीदारी दर्ज करायी। तत्कालीन समय में एक प्रसिद्ध अधिवक्ता के रूप में ख्यातप्राप्ति श्री गोपाल दास शर्मा जनपद में काँग्रेस की उदारवादी नीति के प्रबल प्रवक्ता थे।

जनपद के प्रारम्भिक कांग्रेसियों में प्रसिद्ध शर्मा जी सन् 1892 के काँग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के पश्चात् सन् 1916 ई० तक लगातार काँग्रेस के अधिवेशनों में जनपद का प्रतिनिधित्व करते रहे। वे संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे, तथा काँग्रेस के उन उदारवादी नेताओं के समर्थक थे जो देश की स्वशासन

व्यवस्था को अंग्रेजी शासन द्वारा विकसित करना चाहते थे।

सन् 1907 में जब सूरत अधिवेशन में काँग्रेस में दो गुट हो गये तब भी शर्मा जी ने उदारनीति के अनुसरणकर्ता गोपाल कृष्ण गोखले का समर्थन किया। आप 1903 में नगर पालिका उरई के सदस्य हुए। पहले गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में और तत्पश्चात निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में सक्रिय सेवायें प्रदान करते हुए लगातार काँग्रेस की उदारवादी नीतियों का प्रचार-प्रसार जनपद में बनाये रखा। उन्होंने जनपद का आरम्भिक विकास करने के लिए जिला जालौन सहकारी बैंक व अनाथालय का भी बीजारोपण किया। सन् 1916 में आपने काँग्रेस छोड़कर श्री सप्तु व चिन्तामणि द्वारा स्थापित भारतीय उदार संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली, क्योंकि आपका मन काँग्रेस में बढ़ते उग्रवादी प्रभाव के चलते द्रवित हो उठा था। शर्मा जी का दृष्टिकोण समाज सेवा के क्षेत्र में ज्यादा उदार था इसी के चलते उनका मत था कि **“राजनीति के कारण समाज सेवा के अन्य क्षेत्र को उपेक्षित न कर उनमें सक्रिय सहयोग देना चाहिए।”** अपने स्वयं सेवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण जिले में पड़े भीषण अकाल के समय सर्वेंट ऑफ इण्डिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने राहत कार्यों में अकथनीय परिश्रम किया। जिससे उनकी अथक परिश्रमी सेवाओं से खुश हो ब्रिटिश सरकार ने सन् 1911 ई० में आपको ‘राय साहब’ की उपाधि से विभूषित किया।

उदारवादी युग के प्रमुख जनपदीय नेता

जनपद में उदारवादी नीति के प्राण कहे जाने वाले राय साहब गोपालदास शर्मा का आगमन सन् 1900 ई० में उरई में एक अधिवक्ता के रूप में हुआ। आपका जन्म ग्वालियर रियासत के बराना गाँव में पुष्करणा ब्राह्मण व प्रबल आर्यसमाजी

समर्थक श्री प्रागदास के यहाँ सन् 1873 में हुआ था। 20 वीं सदी के प्रारम्भ में झाँसी से वकालत की सफल शुरुवात करने के पश्चात एक सफल एवं ख्याति प्राप्ति अधिवक्ता के रूप में आपने उरई में अपना जीवन प्रारम्भ किया।

आपका तांबई रंग, भरा चेहरा एवं सुगठित शरीर और उस पर चेहरे में सफेद मूँछे उन्हें सचमुच रायसाहब की उपाधि को अभिव्यक्त करती थी। आपके व्यवहार के सलीके एवं सेवा भाव से प्रेरित हो, नगरवासी उनके गलियों से गुजरते ही सम्मान में खड़े हो जाते थे। आपने जनपद में एक प्रतिष्ठित वकील की ख्याति प्राप्त करते हुए सन् 1892 में काँग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में जनपद का प्रतिनिधित्व स्वयं सेवक बनकर किया। और लगातार सन् 1916 ई० तक अपने इसी रूप में काँग्रेस सम्मेलनों में भाग लेकर देशप्रेम व उदारवादी नीतियों का अनुसरण कर अपनी राष्ट्र श्रद्धा को अभिव्यक्त किया।

रायसाहब शर्मा जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुवात सन् 1903 में उरई नगर पालिका के सदस्य के रूप में की। तत्पश्चात प्रथम गैर सरकारी सभापति व बाद में निर्वाचित अध्यक्ष बनकर अपने को जनसेवा के लिए प्रस्तुत किया। सन् 1918 में झाँसी मण्डल से काउन्सिल के सदस्य बने तथा सन् 1920 में जालौन जिले के लिए गठित विद्यायी काउन्सिल का सदस्य बनकर आपने सूखाग्रस्त समस्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा जलआपूर्ति की व्यवस्था कर एक सच्चे राजनेता का दायित्व निभाया था। जनपद में पड़े भीषण अकाल एवं सूखा के दौरान सर्वेंट ऑफ इण्डिया सोसाइटी की ओर से किये गये राहत कार्यों में आपके अथक परिश्रम से खुश हो तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें **‘रायसाहब’** की उपाधि एवं सन् 1926 में ‘रायबहादुर’ की उपाधि देकर सम्मानित किया गया था।

अपने पिता से ग्रहण कर सेवाधर्मी स्वभाव के रायबहादुर गोपाल दास शर्मा जी के द्वारा

नगर पालिका, गौशाला, बार एसोसिएशन, जिला सहकारी बैंक, आर्य समाज आदि के अध्यक्ष पद सुशोभित हो आपने इन अध्यक्षी दायित्वों का निर्वाहन बड़े ही परिश्रम व तन्मयता से निभाये। आपके द्वारा नगर व जनपद के विकास के लिए अनाथालय, अछूत पाठशाला, विधवा आश्रम, धर्मशाला, गोशाला, जिला को ऑपरेटिव बैंक, डी०ए०वी० स्कूल की संस्थापना, आर्य समाज भवन, शमशान घाट में विश्राम स्थल, नगर में अनेक कुओं आदि के अनेक भवनों का निर्माण कार्य कराया गया। आपके इस स्थापत्य कला को देखकर तत्कालीन जनता द्वारा उन्हें नगर के शाहजहाँ के रूप में भी जाना जाता था। धार्मिक प्रवृत्ति के शर्मा जी भगवत गीता के अनन्य उपासक एवं कुशल पाठक थे। तत्कालीन समय में डिप्टीगंज में होने वाली रामलीला में आप विश्वामित्र व परशुराम का पाठ करने में पारंगत तथा हास्य रस के चलते फिरते शब्दकोष थे। इस अथक परिश्रम, धर्मप्राण एवं सफल जनप्रतिनिधि का देहान्त 17 फरवरी सन् 1931 को अपना सबसे प्रिय गीता पाठ सुनते-सुनते हो गया।

उग्रवादी आन्दोलन का जन्म एवं जनपद-जालौन की भूमिका (सन् 1905-16)

उग्रवादी आन्दोलन –“विरोधपत्रों और प्रार्थनाओं के दिन लड़ चुके हैं। केवल विरोधपत्रों से जिनके पीछे आत्मविश्वास का बल न हो जनता का भला नहीं हो सकता। यह आशा करना निरर्थक है कि हमारी प्रार्थनाओं पर विचार किया जाएगा, जब तककि प्रार्थनाओं के पीछे दृढ़ संकल्प का बल न हो।” –लोकमान्य तिलक

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में उन उदार राष्ट्रवादियों के प्रभाव में थी, जिनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमिक सुधार करना था और जो इस लक्ष्य की

प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों के प्रयोग में विश्वास करते थे। लेकिन सन् 1885 ई० से सन् 1905 ई० के दौरान भारत व विदेशों में कुछ ऐसी घटनाओं घटित हुईं और कुछ ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील हुईं जिन्होंने भारतीय युवा वर्ग को पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग के लिए प्रेरित किया। पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग और उसकी प्राप्ति हेतु जन-आन्दोलन के मार्ग को अपनाने वाली इस धारा को ही ‘उग्रवादी आन्दोलन’ के नाम से जाना जाता है। इस उग्रवादी आन्दोलन का उदय न तो आकस्मिक था और न अन्य परिस्थितियों से अलग एक पृथक परिवर्तन, वरन् यह तो विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों और शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम था।

बंगाल का विभाजन (सन् 1905)

लार्ड कर्जन द्वारा सन् 1905 ई० में किया गया बंगाल का विभाजन, उनके सबसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में एक माना जाता है। यद्यपि बंगाल के विभाजन से कर्जन का उद्देश्य बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कुचल देना था, लेकिन व्यवहार में इस कार्य के परिणाम स्वरूप न केवल बंगाल, वरन् सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की अभूतपूर्व भावना को जन्म दिया। श्री ए०सी० मजूमदार के अनुसार लार्ड कर्जन हर जगह प्रमुख मुसलमानों से मिले और चटगाँव व ढाका में मुसलमानों की बड़ी सभाएं कर उन्हें यह समझाया कि “बंगाल विभाजन में मेरा उद्देश्य प्रशासकीय सुविधा भर देखना नहीं है, मैं एक मुस्लिम प्रान्त बनाना चाहता हूँ, जहाँ इस्लाम के अनुयायियों का बोलबाला होगा। विभाजन से पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को वह एकता प्राप्त होगी जो मुसलमान बादशाहों और सूबेदारों के राज के बाद उन्हें कभी नसीब नहीं हुई थी।”⁽⁵⁾ इसी पूर्वी बंगाल में नियुक्त गवर्नर सर बैम्फाइल्ड ने कहा कि –“उसकी दो स्त्रियाँ हैं एक हिन्दू और दूसरी मुसलमान, किन्तु वह दूसरी को अधिक चाहता

है।⁽⁶⁾ यद्यपि अंग्रेजी शासन ने बंगाल विभाजन का औचित्य सिद्ध करने तथा मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की परन्तु बंगाल का विभाजन उग्रवादी आन्दोलनकारियों को सोते हुए व्यक्ति को जबरदस्ती जगाने की भाँति रहा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल में ही सबसे पहले तीव्र आन्दोलन शुरू हो, जो शीघ्र ही लगभग सम्पूर्ण भारत में फैल गया। ऐनी बेसेन्ट ने इस सन्दर्भ में सच ही कहा है कि **“सारा भारत राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ।”** विभाजन के विरोध की भावना सम्पूर्ण देश में इतनी तीव्र थी कि 16 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने आन्दोलन का दमन करने की भरसक कोशिश की, लेकिन आन्दोलन दिन व दिन जोर ही पकड़ता गया। सभाएँ, प्रदर्शन और हड़तालें सामाजिक जीवन का सामान्य अंग बन गयीं।

सन् 1905 का बनारस अधिवेशन

भारतीय राजनीति में उग्रवादी तत्वों के उदय से काँग्रेस संगठन का प्रभावित होना नितान्त स्वाभाविक था। सन् 1905 के बनारस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों के उग्रवादी वर्ग ने उदारवादियों की ‘राजनीतिक भिक्षावृत्ति’ की नीति की तीव्र निन्दा की और इस लक्ष्य का प्रतिपादन किया कि संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध के मार्ग को अपना कर ही भारत के राष्ट्रीय जीवन पर विदेशी नौकरशाही के प्रभुत्व का अन्त नहीं किया जा सकता है। इसी अधिवेशन में काँग्रेस के दोनों वर्गों द्वारा **‘स्वराज्य’** की माँग की अपने-अपने ढंग से व्याख्या की गयी। उदारवादियों के अनुसार इसका तात्पर्य ‘औपनिवेशिक आधार पर स्वशासन’ था, जबकि उग्रवादी इसका आशय ‘पूर्ण एवं निर्बाध स्वतन्त्रता’ से लेते थे। इस अधिवेशन से तिलक ने ‘उग्रवादी दल’ की स्थापना का मन बना लिया था।

काँग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन (सन् 1906)

बंगाल विभाजन के कारण बंगाल सहित सम्पूर्ण भारत की राजनीति उबाल की स्थिति में थी जिससे काँग्रेस के अन्दर उग्रवादियों और उदारवादियों में परस्पर मतभेद बढ़ते ही जा रहे थे। उग्रवादी, तिलक को कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर अपने नीतियों को काँग्रेस के कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करवाना चाहते थे लेकिन उदारवादी किसी भी हालात पर इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जिससे दोनों दलों में जो मतभेद व्याप्त था, उसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी तथा सन् 1906 के शीतकाल तक यह मतभेद ऐसा उग्र हो गया कि 81 वर्ष के वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौरोजी को इंग्लैण्ड से भारत बुलाकर अध्यक्ष बनाने के अतिरिक्त काँग्रेस का अधिवेशन करना असम्भव प्रतीत हो रहा था। दादाभाई नौरोजी ने भारत एवं काँग्रेस की स्थिति को पहचानकर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दूरदर्शिता से काम लिया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण का प्रारम्भ सर हेनरी बैरनमेन के इस वाक्य से किया कि **“सुराज्य किसी दशा में स्वराज्य का स्थानापन्न नहीं हो सकता है।”** उन्होंने बड़ी चतुराई से काँग्रेस के मंच से ही **‘स्वराज्य’** शब्द का प्रयोग कर स्पष्ट रूप से इसे भारत का अन्तिम राजनीतिक लक्ष्य घोषित कर दिया। काँग्रेस अधिवेशन में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होना वस्तुतः उग्रवादी दल की विजय ही थी।⁽⁷⁾

सूरत की फूट (1907)

कलकत्ता के सन् 1906 के काँग्रेस अधिवेशन में ‘स्वराज्य’ प्राप्ति के लक्ष्य की घोषणा की गयी थी लेकिन काँग्रेस का उदारवादी पक्ष स्वराज्य प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का आन्दोलन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसके अलावा उदारवादी

नेता 'स्वराज्य' की व्याख्या इस तरीके से कर रहे थे जिसमें स्वराज्य की मुख्य भावना व लक्ष्य का ही लोप था। उधर उग्रवादी इस प्रयत्न में थे कि सन् 1906 की काँग्रेस की घोषणाओं में उदारवादी भी अमल करें और स्वराज्य प्राप्ति के लिए सक्रिय आन्दोलन में सहयोग करें। उग्रवादी विदेशी वस्तुओं के अतिरिक्त सरकारी नौकरियों और संस्थाओं का भी बहिष्कार करना चाहते थे। कलकत्ता अधिवेशन की भाँति इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष पद को लेकर भी काफी विवाद हुआ। फलतः उदार दल के आधार स्तम्भ रास बिहारी घोष को इस अधिवेशन का सभापति नियुक्ति किया गया। पारस्परिक विरोध की इस स्थिति में काँग्रेस का सम्मेलन शोर गुल का निन्दनीय अधिवेशन बन गया। जिससे व्यथित हो ऐनी बेसेन्ट ने सत्य ही कहा है कि **“सूरत घटना काँग्रेस की कहानी की सबसे दुःखद घटना थी।”**⁽⁸⁾ सूरत अधिवेशन में पड़ी फूट के चलते सन् 1916 तक उग्रवादी काँग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए जिससे इस समय तक काँग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व बना रहा। सन् 1916 में इन दोनों पक्षों में समझौता हुआ और उसके परिणाम स्वरूप ये दोनों दल पुनः सम्मिलित रूप से स्वतन्त्रता आन्दोलन के कार्य करने लगे।

अंग्रेजी शासन और उग्रवादी आन्दोलन

उदारवादी अंग्रेजी शासन के प्रति राजभक्ति और वैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे, जिससे ब्रिटिश शासन इन उदारवादियों के विरुद्ध होते हुए भी काफी सीमा तक इनके प्रति सहिष्णु बना रहा। किन्तु 20वीं सदी के प्रारम्भ से ही देश में उग्र राष्ट्रियता की जो लहर उठी थी अंग्रेजी सरकार को उसे सहन कर पाना असम्भव था। शासन द्वारा इन उग्रवादियों का दमन करने के लिए विभिन्न कानूनों की व्यवस्था की गयी। जिससे 'इण्डियन पीनल कोड' में नयी धारा 124 ए और 153 ए जोड़ी गयी। एक अन्य विशेष

अधिनियम द्वारा अधिकारियों को यह शक्ति दी गयी कि वे जिन राजनीतिक संगठनों को सरकार विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाये उन पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों से शासन ने उग्रवादियों का दमन करना प्रारम्भ कर दिया। इस दमन कार्यवाही के अर्न्तगत रूसी सरकार की पद्धति पर प्रमुख उग्रवादी नेताओं को निर्वासित कर दिया गया। मई सन् 1907 में पंजाब के लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को बिना मुकदमा चलाये ही माण्डले जेल में डाल दिया गया। 'केसरी' में छपे हुए कुछ लेखों के आधार पर सन् 1908 में लोकमान्य तिलक को कठोर कारावास दिया गया। बंगाल में अनेक व्यक्तियों पर आंतकवादी कार्यों के लिए मुकदमा चलाकर दण्डित किया गया। अनेक पत्र एवं पत्रों के सम्पादकों एवं प्रकाशकों को भी इसी प्रकार दण्डित किया गया।

राजनीतिक लक्ष्य और विचारधारा की दृष्टि से तो उग्रवादी उदारवादियों से काफी भिन्न थे ही पर इन दोनों में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अन्तर साधन सम्बन्धी भिन्नता का था। नेविन्सन ने तिलक को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि—**“अपने उद्देश्य के कारण नहीं वरन् उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है।”**⁽⁹⁾ उग्रवादियों के बहिष्कार आन्दोलन की मुख्य प्रवृत्ति तो विदेशी वस्तुओं के ही विरुद्ध थी, परन्तु व्यापक व्याख्या में इसमें सरकार के साथ असहयोग, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार भी शामिल था। उग्रवादियों की मान्यता थी कि बहिष्कार विदेशी शासन की प्रतिष्ठा और हितों के ऊपर एक सीधा आघात होगा।

जनपद-जालौन में प्रारम्भिक उग्रवादी गतिविधियाँ (सन् 1905-1916)

उदारवादी युग में जनपद— जालौन लगभग सुसुप्तावस्था के दौर से गुजरा था क्यों कि इस काल अवधि में जनपद में कोई खास गतिविधियाँ नहीं हुई थी। यह दौर केवल गुपचुप तरीके से काँग्रेस के नीतियों के प्रचार—प्रसार के तौर पर बीता था। परन्तु लार्ड कर्जन द्वारा किये गये बंगाल विभाजन ने जनपद को समस्त देश की स्वतन्त्रतावादी उग्र गतिविधियों से जोड़ दिया। आनन्द बिहारी बोस की अध्यक्षता में कलकत्ता के टाउन हाल में प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं की सभा हुई, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार, बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आन्दोलन, शोक सभाओं का आयोजन, उपवास रखना व नंगे पैर चलकर हिन्दू—मुस्लिम आपस में एक दूसरे को राखी बाँधे व देश भर में वन्दे मातरम् के जुलूस निकालने आदि निर्णय लिये गये। इन गतिविधियों से आन्दोलनकारियों को यह विश्वास था कि इससे जनता में आपस में आत्मनिर्भरता, स्वाभिवान और धार्मिक एकता स्थापित होने के साथ—साथ अंग्रेजी हुकूमत पर आर्थिक दबाव व राजनैतिक प्रतिरोध करने का एक सशक्त हथियार जनता को प्राप्त होगा।

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात यह पहला वाक्या था जब सम्पूर्ण देश का जनमानस बंगाल विभाजन के विरोध में एक साथ संगठित होकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था।⁽¹⁰⁾ इस असन्तोष को एकजुटता प्रदान करने में बाल गंगाधर तिलक के कथनों **“जब आप स्वदेशी स्वीकार करते हैं तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व त्याग अवश्य करना ही होगा।”** तथा **“स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे।”** ने आग में घी डालने का काम किया। जिससे सम्पूर्ण भारत वर्ष में बंगाल विभाजन के खिलाफ उग्रवादी आन्दोलन की शुरुवात होने लगी। इस उग्रवादी आन्दोलन का प्रादुर्भाव करने में तिलक का साथ लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र ने दिया। जिससे यह लाल,

बाल व पाल का तिकड़ी उग्रवादी आन्दोलन का सूत्रधार बनकर राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा को बदलने में काफी हद तक सफल रही। हालांकि प्रारम्भ में काँग्रेस द्वारा इसका प्रबल विरोध हुआ परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतिहास में इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी।

बंगाल विभाजन की खबर सारे देश में जंगल में आग के समान फैलने लगी, जिसकी एक चिंगारी बेनीमाधव तिवारी नामक नवयुवक के रूप में जनपद जालौन में भी भड़क उठी। हालांकि यह बालक अपनी किशोरावस्था में कदम रख रहा था परन्तु कानपुर के राम प्रसाद मिश्र का सानिध्य पाकर द्रवित हो उठा। मिश्र जी के यहाँ हो रही बंगाल विभाजन की परिचर्चाओं को सुन इस किशोर ने बंगाल विभाजन की अंग्रेजों की छदम चाल का विरोध कविता की पक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यह बेनी माधव के राजनैतिक जागृति का आरंभिक दौर था। इस अभिव्यक्त ने जनपद में राजनैतिक चेतना के उग्रवादी विचारों बीजारोपण किया और इसका प्रारम्भ जनपद में विदेशी वस्त्रों की होली जला कर किया गया था। इस प्रकार जनपद में उग्रवादी विचारों की शुरुआत इन्हीं प्रारम्भिक गतिविधियों से प्रारम्भ हुई।

काँग्रेस का उदारवादी गुट लाल, बाल, पाल की तिकड़ी के कार्यप्रणाली को हजम नहीं कर पा रहा था जिसकी अभिव्यक्ति सन् 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दिखने लगी थी। यह अभिव्यक्ति सन् 1907 के काँग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आयी जो इतिहास में काँग्रेस के सूरत विभाजन के रूप में दर्ज हुई। कलकत्ता अधिवेशन में ही उग्रपंथियों के प्रभाव से ही स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा का बहिष्कार एवं स्वराज्य आदि प्रस्तावों को एक तरह से दुखी मन से उदारवादियों द्वारा स्वीकार किये गये थे। अतः यह दुखीमन एवं उग्रस्वभाव का खुलकर सामना सूरत अधिवेशन में हुआ। जिसमें काँग्रेस ने अपनी

उत्पत्ति के 22 वें वर्ष मर्यादा की सभी हदें पार कर दी। यहाँ तक इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों के बयानों के साथ-साथ, कुर्सी-मेज, जूता-चप्पल का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया। हालांकि जनपद का इन सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व नहीं था परन्तु इसकी खबर जनपद के साथ समस्त बुन्देलखण्ड में भी सुनाई दी।

अंग्रेजी सरकार ने इस आपसी फूट का फायदा उठाते हुए जहाँ उदारवादियों को प्रोत्साहन दिया वहीं उग्रवादियों के प्रति कठोर कार्यवाही करके उनको दबाने का पूरा प्रयत्न किया। सूरत अधिवेशन से विभाजित काँग्रेस के दोनों उग्र व उदार दल अपनी-अपनी पृथक सभायें आयोजित करने लगे और अब भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का संचालन दो पृथक विचारों द्वारा होने लगा। यह पृथक्य काँग्रेस के लिए तो बुरा दौर था परन्तु इससे स्वतन्त्रता आन्दोलन में अधिक सक्रियता आयी जो स्वतन्त्रता प्राप्ति की सफलता में काफी कारगर सिद्ध हुई। राष्ट्र ने पहली बार यह अनुभव किया कि उग्रवादी तरीके से कुशासन जैसी बुराई को समाप्त किया जा सकता है अतः इस आन्दोलन ने भविष्य में होने वाले आन्दोलनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी।⁽¹¹⁾

तिलक द्वारा सम्पादित पत्र 'केसरी' व 'मराठा' उग्रवादियों को अपने विचारों को व्यक्त करने तथा जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में काफी महती भूमिका निभा रहे थे। इसी समय जनपद-जालौन में उग्रवादी विचार धारा का राष्ट्रीय पत्र कहे जाने वाले साप्ताहिक उत्साह का प्रकाशन कोंच के शंभु दयाल शशांक द्वारा किया गया। उरई से प्रकाशित इस पत्र के प्रारम्भिक प्रकाशक बलदेव प्रसाद पालीवाल (डकोर) व सम्पादक शंभु दयाल जी थे।⁽¹²⁾ प्रारम्भिक उग्रवादी आन्दोलन के समय भारतीय जनता और जनपद वासियों के स्वतन्त्र विचारों को व्यक्त करने का मंच जो शशांक जी

द्वारा दिया गया वह वाक्यी काबिले तारीफ था। इस पत्र के माध्यम से स्वतन्त्रता का शंखनाद, राष्ट्रीय भावनाओं एवं देशप्रेम से भरी कविताओं का प्रकाशन किया गया। 'सत्य प्रकाश' नामक मासिक पत्र जनपद-जालौन का प्रथम मासिक पत्र था जिसका प्रकाशन कोंच में सन् 1912 ई0 में किया गया था। यह पत्र आकार में 8 इंच गुणा 6 इंच का था। यह देश में हिन्दी में प्रकाशित होने वाले तीन पत्रों में प्रमुख एक था। कोंच से ही सन् 1913 में श्री कृष्ण गोपाल शर्मा (चौबे जी) ने 'साप्ताहिक भाष्कर' का प्रकाशन का प्रारम्भ किया। यह साप्ताहिक पत्र लगभग दो वर्ष प्रकाशित होता रहा, व जनपद में राष्ट्रीय जागृति का यह प्रारम्भिक प्रस्फुटन था। राष्ट्रीय विचारधारा के प्रबल समर्थक, काँग्रेस की उग्रवादी आन्दोलनात्मक गतिविधियों के सक्रिय हस्ताक्षर व प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी शर्मा जी के झाँसी जाने व वहाँ आन्दोलन का अपना कार्यक्षेत्र बना लेने के कारण अब 'भाष्कर' का प्रकाशन झाँसी से होने लगा था। झाँसी में रहकर शर्मा जी ने स्वतन्त्रता आन्दोलनों में अपनी उपस्थिति एक कुशल एवं प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में दर्ज कराते रहे।

'भाष्कर' के झाँसी स्थानान्तरण में लगा जनपद-जालौन में पत्रों का अभाव हो जायेगा परन्तु ऐसा सम्भव न हो सका क्यों कि अपनी देश प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करने की इच्छाओं की परिणति 'देहाती' के रूप हुई। 'देहाती' उरई से सन् 1913 में सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री बृजबिहारी मेहरोत्रा द्वारा प्रकाशित किया गया। यह साप्ताहिक पत्र अपने प्रकाशन के प्रारम्भिक महीनों से ही क्रान्तिकारी व उग्रवादी गतिविधियों में विश्वास करने वाले नवयुवकों में लोकप्रिय हो गया। मेहरोत्रा जी के पश्चात देहाती का प्रकाशन जनपद के तत्कालीन प्रमुख राजनेता श्री बेनी माधव तिवारी ने किया 'देहाती' में सन् 1922 में प्रकाशित अग्र लेख जो लाल स्याही में छापा गया था के कारण तिवारी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला जिसमें उन्हें तीन वर्ष की जेल

की सजा भुगतनी पड़ी। यह जनपद की प्रथम घटना थी, जिसमें किसी साप्ताहिक पत्र के प्रकाशित लेख के आधार पर लेखक पर सरकार द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया हो तथा सम्पादक को विधिवत सजा सुनाई गयी हो।⁽¹³⁾

एक स्थानीय व्यापारी नेता रामचन्द्र अग्रवाल उर्फ चंदीबाबू के सहयोग से सन् 1917 में साप्ताहिक 'उदबोधन पत्र' निकाला गया। यह पत्र प्रारम्भ में हस्तलिपि में प्रकाशित होता था तथा गुप्त रूप से स्थानीय उग्रवादी गतिविधियों में सक्रिय लोगों तक पहुँचाया जाता था। बाद में माहिल तालाब के सामने स्थित चंदीबाबू के हाते में एक गोपनीय छापाखाना लगाया गया, जिसमें जनपद के सभी क्षेत्र में स्वतन्त्रता एवं देशप्रेम की भावनाओं से छपे पत्र गुप्त रूप से छापकर वितरित किये जाते थे। इस तरह से जनपद में समाचार पत्रों के प्रकाशन से जनता में उग्रवादी गतिविधियों के बीज बोए जाने लगे।

यह उग्रवादी गतिविधियाँ जनपदीय जनता में पनपकर बाहर की ओर मुखातिब हो ही रही थी कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया। विश्व युद्ध के प्रारम्भ होते ही गाँधी जी के आदेश से सम्पूर्ण देश में रंगरूटों की भर्ती प्रारम्भ की गयी। जिसके लिए प्रत्येक जनपद में भर्ती के लिए भर्ती अफसर (रिक्रूटमेंट) बनाये गये। जनपद-जालौन में यह कार्य मन्नीलाल पाण्डेय व बेनीमाधव तिवारी को सौंपा गया। कालपी में इस कार्य का निर्वहन मातादीन पुरवार द्वारा किया गया था। इस भर्ती से जनपदीय जनता अजीब दुविधा की स्थिति में थी क्योंकि एक ओर स्वदेशी एवं स्वराज्य, तथा विदेशी वस्तुओं की होली जैसे आन्दोलन सक्रिय थे वहीं दूसरी ओर गाँधी जी द्वारा अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए भारतीय को सहयोग देने का आदेश दिया गया। इस ऊहापोह की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उरई क्लब के मैदान में कलकटर लिडियार्ड की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया

गया। तत्कालीन काँग्रेस कार्यकर्ताओं का वर्ग भी इस भर्ती से भ्रम की स्थिति में था। इस विशाल सभा में पाण्डेय जी द्वारा भर्ती की स्थिति को स्पष्ट करते हुए बतलाया कि हम लोग इस शर्त के आधार पर गोरी सरकार को समर्थन कर रहे हैं कि युद्ध में विजय प्राप्त होने पर हमें स्वराज्य प्रदान कर दिया जायेगा। तिवारी जी ने स्थिति को अत्यधिक स्पष्ट करते हुए बताया व समझाया कि गाँधी जी के अनुसार युद्ध में विजय के बाद स्वराज्य मिल जायेगा व उपस्थित अधिकारी हम भारतीयों के मातहत होंगे। जनता को स्पष्ट दिशा निर्देश मिलते ही क्लब का मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। जनता का सहयोग पा सरकारी व अंग्रेज अधिकारियों ने भी राहत की साँस ली।

गृहशासन आन्दोलन एवं जनपद-जालौन (सन् 1915-17)

आयरलैण्ड में आयरिश नेता रेडमाण्ड के नेतृत्व में 'गृहशासन' (होमरूल) लीग की स्थापना हुई थी। जो वैधानिक और शान्तिमय उपायों से आयरलैण्ड के लिए होमरूल या गृहशासन प्राप्त कराना चाहती थी। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट जो स्वयं एक आयरिश महिला थी, आयरलैण्ड की भाँति भारत में भी 'गृहशासन आन्दोलन' चलाना चाहती थी। गृहशासन आन्दोलन को सक्रिय करने के लिए वे स्वयं काँग्रेस में शामिल हुईं और उदारवादियों तथा उग्रवादियों को एकताबद्ध कर 'होमरूल आन्दोलन' चलाया। भारत में गृहशासन आन्दोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक और श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के द्वारा ही मुख्य रूप से किया गया।

गृहशासन आन्दोलन एक वैधानिक आन्दोलन था। इसका सर्वप्रथम उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। इस सन्दर्भ में ऐनी बेसेन्ट ने अपने पत्र 'कामन व्हील' में लिखा था "राजनीतिक सुधारों से हमारा उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला नगरपालिकाओं तथा

विधान सभाओं तक राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना है। इस राष्ट्रीय संसद के अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की धारा-सभाओं के समान ही होंगे, इसे नाम चाहे जो भी दिया जाय और जब ब्रिटिश साम्राज्य की संसद में स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि लिये जायें, तो भारत का प्रतिनिधि भी उस संसद में पहुँचें।⁽¹⁴⁾

श्रीमती ऐनी बेसेन्ट की गतिविधियाँ ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधी नहीं थी और न ही आन्दोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना या उनके युद्ध प्रयत्नों में बाधा डालना था। इसके विपरीत यह आन्दोलन तो इस विचार पर आधारित था कि 'स्वशासित भारत साम्राज्य के लिए युद्ध में अधिक सहायक हो सकेगा।' इस प्रकार वह युद्ध में परोक्ष रूप अंग्रेजों की सहायता देकर गृहशासन लाना चाहती थी। ग्रहशासन आन्दोलन का एक उद्देश्य भारतीय राजनीति की तत्कालीन बढ़ रही उग्रवादी धारा को सुनियोजित करना था। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने तत्कालीन भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था और पाया कि यदि शान्तिपूर्ण और वैधानिक आन्दोलन प्रारम्भ नहीं किया गया, तो भारतीय राजनीति पर क्रान्तिकारियों और आंतकवादियों का आधिपत्य स्थापित हो जायगा। इसलिए उन्होंने शान्तिपूर्ण एवं वैधानिक ढंग से गृहशासन आन्दोलन चलाना अधिक श्रेयस्कर समझा। ग्रहशासन आन्दोलन भारत के लिए स्वशासन की याचना नहीं, वरन् अधिकार पूर्ण माँग की अभिव्यक्ति था। ग्रहशासन आन्दोलन के द्वारा ही सर्वप्रथम अधिकारों की माँग ब्रिटिश शासन के समक्ष सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत की गयी। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट का कथन था कि "ग्रहशासन भारत का अधिकार है और राजभक्ति के पुरस्कार रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मूर्खतापूर्ण है। भारत ग्रहशासन को युद्ध के पूर्व माँगता था, भारत इसे युद्ध के बीच माँग रहा है और युद्ध के

बाद भी माँगगा। परन्तु वह इस न्याय को एक पुरस्कार के रूप में नहीं वरन् अधिकार के रूप में माँगता है इस बारे में किसी की कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए।"⁽¹⁵⁾

मार्च सन् 1916 में लोकमान्य तिलक ने 'महाराष्ट्र होमरूल लीग' की स्थापना करने ग्रहशासन का प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् 1 सितम्बर सन् 1916 को ऐनी बेसेन्ट ने मद्रास में 'अखिल भारतीय होमरूल लीग' की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने ऐनी बेसेन्ट को पूरा सहयोग दिया और ये दोनों नेता सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संगठित रूप से कार्य करने लगे। आन्दोलन के प्रवर्तकों ने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किये। दोनों नेताओं ने पूरे भारत के छोटे-बड़े शहरों का दौरा कर सभायें आयोजित की। अपने भाषणों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से ग्रहशासन की माँग पर जोर दिया। ऐनी बेसेन्ट ने अपने दैनिक पत्र 'न्यूइण्डिया' और साप्ताहिक पत्र 'कामन व्हील' के माध्यम से ग्रहशासन आन्दोलन का प्रचार प्रसार प्रारम्भ कर दिया। तिलक ने भी अपने पत्रों 'केसरी' और 'मराठा' के माध्यम से जनता को ग्रहशासन से परिचित कराया। देश के सभी छोटे तथा तथा बड़े नगरों व शहरों में जगह-जगह सभायें आयोजित होनी लगी जिससे आन्दोलन में लगातार उछाल आता गया। 1917 के आरम्भ तक ग्रहशासन आन्दोलन अपने चरम लक्ष्य पर पहुँच गया और इस शान्तिमय एवं वैधानिक आन्दोलन ने सोई हुई भारतीय जनता में अद्भुत जागृति का संचार किया। ग्रहशासन आन्दोलन के बढ़ते प्रभाव तथा क्षेत्र के सम्बन्ध में पं०जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "देश के वातावरण में बिजली सी दौड़ गयी थी और हम नवयुवक एक अजीब उत्साह तथा स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे। हम आशा करते थे कि इसका परिणाम भविष्य में निश्चित कुछ अच्छा होगा।"⁽¹⁶⁾

अंग्रेजी सरकार ग्रहशासन आन्दोलन में अत्यधिक युवा वर्ग की भागीदारी से घबरा उठी और इसे कुचल डालने के प्रयास तेज कर दिये। तिलक और ऐनी बेसेन्ट के कार्य-कलापों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। तिलक को ब्रिटिश शासन द्वारा आदेश दिया गया कि वह एक वर्ष के लिए अपनी सभी राजनीतिक गतिविधियाँ बन्द कर दे। तिलक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिससे सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। ग्रहशासन आन्दोलन का ज्यादातर प्रचार समाचार पत्रों के माध्यम से हो रहा था अतः सरकार ने प्रचार को रोकने के लिए दमनमूलक प्रेस एक्ट का खुलकर प्रयोग किया। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट से, जिनका 'न्यू इण्डिया' और 'कामन व्हील' ग्रहशासन आन्दोलन का जोर-शोर से प्रचार कर रहे थे, प्रेस और पत्र के लिए 20 हजार रुपये की जमानत राशि माँगी गयी थी जिसे सरकार ने जब्त कर लिया। तत्कालीन लार्ड पैटलैण्ड की सरकार ने सन् 1917 के प्रारम्भ में 'सरकारी आज्ञा पत्र नं० 559' के अनुसार विद्यार्थियों तथा नवयुवकों को राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने से प्रतिबन्ध लगा दिया एवं ग्रहशासन आन्दोलन की सभाओं, गोष्ठियों आदि में प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया गया।⁽¹⁷⁾

ब्रिटिश सरकार की दमन पूर्ण नीतियाँ उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी, जब तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश के लिए प्रतिबन्धित कर दिया और श्रीऐनी बेसेन्ट को उनके दो घनिष्ठ सहयोगियों जी०एस० अरूडेल और वी०पी० वाडिया सहित नजरबन्द कर दिया गया। सरकारी सोच थी कि इन दमनपूर्ण कार्यों से आन्दोलन ठण्डा पड़ जायेगा किन्तु इन दमनपूर्ण कार्यवाहियों ने आन्दोलन की अग्नि में आहुति का कार्य किया।

इधर सन् 1916 में मुस्लिम लीग काँग्रेस में समझौता हो जाने, काँग्रेस में एकता स्थापित

होने और काँग्रेस में उग्रवादी दल का प्रभुत्व स्थापित हो जाने, भारतीयों द्वारा संयुक्त रूप से ग्रहशासन की माँग की जाने और अन्तिम रूप में मेसोपोटेमिया आयोग की रिपोर्ट (सन् 1917) ने अंग्रेजी सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर शासन में भारतीयों की भागीदारी की निश्चित घोषणा की जाय। नवनियुक्त भारत मंत्री मि० माण्टेग्यू प्रगतिशील एवं भविष्यवादी दृष्टिकोण के थे अतः उन्होंने तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त सन् 1917 को घोषणा की कि—“साम्राज्य की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूरी तरह सहमत है, यह है कि शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को आधिकाधिक साथ लिया जाय, तथा स्वशासन के कार्य में लगी हुई संस्थाओं को उत्साहित किया जाय, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके।”

घोषणा पत्र में एक ओर जहाँ यह उत्साहवर्धक बात थी कि भारत में अंग्रेजी शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना है, वहाँ इसके साथ ही यह निराशा जनक बात भी जोड़ दी गयी थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप से ही हो सकेगी और प्रत्येक नवीनचरण की प्रकृति और समय का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह कहकर कि भविष्य का विकास भारतीयों के सहयोग उनके द्वारा प्रदर्शित सहयोग की भावना पर निर्भर करता है, भारतीयों को असहयोग के विरुद्ध एक स्पष्ट धमकी भी दे दी गयी थी। किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सन् 1917 की घोषणा ने भारतीय शासन में ग्रहशासन के विकास के लिए एक नवीन युग का आरम्भ कर दिया। अगस्त 1917 के पूर्व अंग्रेजी शासन द्वारा भारत के सम्बन्ध में कुछ उदार घोषणाएं तो की गयी थीं,

किन्तु यह कभी भी नहीं बतलाया गया था कि ब्रिटिश नीति भारत को किस निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर ले जा रही थी। यह कमी सन् 1917 की घोषणा द्वारा पूरी कर दी गयी।

अगस्त सन् 1917 की घोषणा के पूर्व ही श्री मती ऐनी बेसेन्ट को नजर बन्द किये जाने के खिलाफ ग्रहशासन आन्दोलन में मुहम्मद अली जिन्ना जैसे मुस्लिम नेता भी इसमें शामिल हो गये। जनता द्वारा जगह-जगह पर सभाएँ आयोजित कर श्रीमती बेसेन्ट की रिहाई की माँग की। सन् 1917 में भारतमन्त्री लार्ड माण्टेग्यू ने अपनी घोषणा के साथ ही ग्रहशासन आन्दोलन के प्रमुख नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने ग्रहशासन के आन्दोलन के सन्दर्भ में लिखा—“आंग्ल भारतीय इतिहास के पृष्ठ टूटी हुई प्रतिज्ञाओं के खण्डों से भरे पड़े हैं, परन्तु शायद अब एक नूतन अध्याय आरम्भ होने को था।”⁽¹⁸⁾

जनपद जालौन में ग्रहशासन की गतिविधियाँ

ग्रहशासन आन्दोलन के द्वारा हवा ने सम्पूर्ण भारत को अपने कब्जे में कर लिया था, इस ग्रहशासनी हवा की लहर जनपद-जालौन में भी दिखाई दी। जनपद-जालौन में ग्रहशासन आन्दोलन की शुरुवात उरई शहर से प्रारम्भ हुई। जनपदीय आन्दोलन के प्रमुख संचालनकर्ता संत स्वभाव के शिक्षक पं० रामाधार जी मिश्र थे। अपने पहनावे से एक आध्यात्मिक व्यक्ति की भांति दिखने वाले मिश्र जी जहाँ भी भ्रमण पर निकल जाते थे वहाँ के माहौल में ऋषितुल्य आध्यात्मिक वातावरण का माहौल बन उठता था। पण्डित जी की आध्यात्म व वेदांत रूपी शिक्षायें हमेशा उनके वक्तव्यों से झलकती रहती थी। यहाँ तक कि वह कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय भी बच्चों को वेदांत व आध्यात्म का महत्व बताना कभी नहीं भूलते थे। वे

बच्चों से अपनी कक्षाओं में अक्सर पूछा करते थे कि अंग्रेज का आई कैपिटल से क्यों लिखा जाता है। कभी कक्षा में कहते कि “मैं होमरूलर होने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हूँ? यह शरीर मेरा होम यानी घर है। इसमें रहने वाला मैं जो वास्तव में इसका स्वामी और शासक हूँ।⁽¹⁹⁾ वह बच्चों को यह वास्तव रूप से अनुभव कराना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर उसका घर होता है। जिस प्रकार शरीर में व्यक्ति (आत्मा) रहती है उसी प्रकार इस देश में हम सभी रह रहे हैं तो यह देश ही हमारा घर है।

जनपद-जालौन में ग्रहशासन के संचालनकर्ता पण्डित रामाधार मिश्र जी के विचारों से प्रेरणा लेकर रायसाहब गोपालदास शर्मा, मन्नीलाल पाण्डेय व कोंच के गौरी शंकर ने जनपद में होमरूल लीग अनेक शाखाएं खोलकर स्वयं को होमरूलर घोषित किया। तिलक व श्रीमती बेसेन्ट के विचारों को कस्बों व गाँवों तक पहुँचाने के लिए अनेक सभाओं का आयोजन किया। मन्नीलाल पाण्डेय ने ग्रहशासन आन्दोलन से जनपद को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जल्द ही वह होमरूल लीग के सक्रिय सदस्य के रूप में उभरें।⁽²⁰⁾ श्रीमती बेसेन्ट के एक विदेशी महिला होते हुए अदम्य साहस से लोगों को परिचित कराते हुए उनके लोकप्रिय पत्र, ‘न्यू इण्डिया’ व ‘कॉमन व्हील’ में प्रकाशित लेखों को जनता के बीच में जाकर उन्हें सुनाने का कार्य जनपद में तीव्र गति से शुरू हो गया। ग्रहशासन आन्दोलन ही जनपद का पहला आन्दोलन था जिसमें सामान्यजन ने रुचि दिखाई व शिक्षित वर्ग के लोगों ने सक्रिय भाग लिया। इस प्रकार सन् 1857 के पश्चात ग्रहशासन आन्दोलन से जालौन के लोगों में पहली बार स्वाधीनता आन्दोलन के प्रति रुचि दिखाई दी थी।

तत्कालीन समय में आर्यसमाजी केदार नाथ के रूप में कालपी में निवास कर रहे पं०

राहुल सांकृत्यायन ने होमरूल के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्ति के अनुसार— “सन् 1917 के आखिरी महीने में होमरूल आन्दोलन जोर पकड़ने लगा था। श्रीमती बेंसेट और उनके सहयोगी अरूडले की नजर बंदी से चारो तरफ सनसनी फैल गयी थी और लोकमान्य तिलक की रिहाई से गर्मदली अंश देश में जोर पकड़ रहा था।” ग्रह शासन आन्दोलन ने जनता को परिचित कराने के लिए पं० वैकटेश नारायण तिवारी ने अनेक छोटी-छोटी पुस्तकों का सम्पादन कर उनके वितरित करना प्रारम्भ कर दिया। ‘भारत भारती’ जो पहले से ही हिन्दी भाषी जनता में लोकप्रिय हो रही थी किन्तु अब उसने राष्ट्रीय संगीत की पुस्तक का रूप भी धारण कर लिया था।

ग्रहशासन आन्दोलन की बढ़ती लोकप्रियता व भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ते असन्तोष से आंशकित होकर अंग्रेजी हुकूमत ने आन्दोलन का दमन करना प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने प्रतिबन्धों द्वारा समस्त संस्थाओं को रोकने का प्रयास किया। भारत में विदेशियों के आवागमन को निषेध कर दिया गया। ‘भारतीय सुरक्षा अधिनियम कानून’ सरकार के लिए सबसे अच्छा हथियार सिद्ध हुआ। इसी कानून का प्रयोग करते हुए सन् 1910 में होमरूल लीग के प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी गयी। छात्रों को इस आन्दोलन से दूर रहने की घोषणा करवा दी गयी। अंग्रेजी शासन के दमन चक्र की पराकाष्ठा उस समय चरम पर पहुंच गई जब तिलक को राज्य के विरुद्ध उकसाने वाले भाषण के आरोप में व ऐनी बेंसेट को धोखे से साक्षात्कार के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। ग्रहशासन आन्दोलन के दोनों शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी से जनता के मन में दबा उबाल भड़क उठा। जनपद के नगर उरई में भी तिलक व ऐनीबेसेन्ट की गिरफ्तारी की आलोचना मन्नीलाल पाण्डेय ने सभा आयोजित कर की तथा जनपदीय जनता से पाण्डेय जी द्वारा ग्रहशासन आन्दोलन में जुड़ने

की जोरदार अपील की गयी थी। जनपद के अग्रणी उदारवादी नेता श्री गोपाल दास शर्मा ने आन्दोलन का उग्ररूप देखकर स्वयं को काँग्रेस से अलगकर लिया तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा सन् 1911 में प्रदत्त ‘रायसाहब’ की उपाधि को त्याग दिया तथा स्वयं को ग्रहशासन आन्दोलन से अलग कर अपना सारा ध्यान नगरपालिका के कार्यों की ओर उन्मुख कर दिया।

रायसाहब गोपालदास शर्मा द्वारा काँग्रेस का साथ छोड़ देने से लगा कि जनपद का ग्रहशासन आन्दोलन खत्म हो जायेगा परन्तु इस आन्दोलन का नेतृत्व दो युवा काँग्रेसी मन्नीलाल पाण्डेय व बेनीमाधव तिवारी द्वारा किया गया। और अगले दो दशक तक जनपद में काँग्रेस का नेतृत्व इन्ही महानुभावों द्वारा संचालित रहा। आर्थिक मन्दी, सरकार की कठोर दमन नीति, और द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार जबरन भर्ती अभियान से ग्रहशासन आन्दोलन के प्रति जनपदीय जनता में उत्साह थम सा गया। परन्तु जनपद के आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला वकील वर्ग एवं शिक्षित लोगों द्वारा छोटी-छोटी सभायें आयोजित कर जनता को आन्दोलन से जोड़े रखा गया। सर्वप्रथम जनपद में सन् 1918 में काँग्रेस की विधिवत् सदस्यता मन्नीलाल पाण्डेय ने उरई, कोंच में गौरीशंकर मिश्र व लल्लूराम मिश्र ने ग्रहण कर जनपद में काँग्रेस की नीतियों का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ किया।⁽²¹⁾ पाण्डेय जी के बढ़ते प्रभाव के चलते उन्हें प्रान्तीय दल का सदस्य बनाया गया एवं बाद में प्रदेश काँग्रेस सेवादल के अध्यक्ष का दायित्व भी दिया गया।

प्रारम्भिक उग्रवादी युग के प्रमुख क्षेत्रीय नेता एवं उनका योगदान

जनपद-जालौन में प्रारम्भिक उग्रवादी गतिविधियाँ (सन् 1905-16) सारे देश के समान अपने

शैशवाकाल से गुजरी थी। इस अन्तराल में न तो कोई व्यापक अभियान छेड़ा गया और न ही गिरपतारियों का दौर चला बल्कि स्थानीय कांग्रेसी नेताओं द्वारा केवल समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सरकार का विरोध किया गया। यह समय जनपद के नेताओं का एक तरह से स्वतन्त्रता आन्दोलन की शिक्षा-दीक्षा का था जिससे जनपदीय जनता को आन्दोलन के लिए तैयार करने एवं अंग्रेजी सरकार की अत्याचार पूर्ण नीतियों से परिचित करा देश के प्रति एकजुटता का भाव पैदा किया गया। इस आन्दोलन में जनपद के प्रमुख नेताओं में पं० बेनीमाधव तिवारी, मन्नीलाल पाण्डेय आदि लोग ही जनपदीय आन्दोलन के सूत्रधार थे।

जनपद के एकमात्र राजद्रोह के मुकदमी पत्रकार पं०बेनीमाधव तिवारी (1890-1952)⁽²²⁾

राजनैतिक चेतना के धनी एवं विलक्षण व्यक्तित्व के पत्रकार पं०बेनीमाधव तिवारी जी का जन्म सन 1890 में ग्राम आटा में पं०अयोध्या प्रसाद तिवारी के घर हुआ था। आप अपनी प्रखर राजनैतिक चेतना एवं व्यक्तित्व से समूचे बुन्देलखण्ड के प्रकाशमान नक्षत्र के समान थे। औपचारिक शिक्षा के अभाव के पश्चात भी आपने लगन एवं स्वाध्यायन से अंग्रेजी भाषा, हिन्दी साहित्य, ज्योतिष एवं पत्रकारिता में महारथ हासिल कर एक बहुआयामी व्यक्तित्व की अनुठी मिसाल पेश की। आपके अन्दर राष्ट्रीय भावना कूट-कूट कर भरी थी जिसके कारण स्वाधीनता आन्दोलन के सम्पूर्ण दौर में पाँच बार जेल यात्रा कर सबसे अधिकतर जेल जाने का गौरव प्राप्त किया। सामाजिक भावनाओं से अभिमुखी एक श्रेष्ठकवि, राष्ट्रप्रेम की भावना से ओत-प्रोत एक निडर पत्रकार, अपने भाषणों में ओजस्वीवाणी के धनी, जीवन के सफल एवं दक्ष अभिनेता व अपनी बात को व्यंग्यात्मक शैली में कहने की अजब कला,

अपनी वाणी से ही लोगों के मनमस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अद्भुत कला आदि तिवारी जी के व्यवहारिक जीवन के विविध पहलू थे।

युवाओं, वंचितों व दलितों के प्रेरणास्रोत, उ०प्र० लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिभावान विधायक, जिलाबोर्ड के निर्वाचित अध्यक्ष, चुनावी दाव-पेंच के मामले में विशेषज्ञ एवं इलेक्शनाचार्य के नाम से ख्याति प्राप्ति पं० बेनीमाधव तिवारी जी चुनावी समय में अक्सर लोगों के मध्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करते सुने जाते थे। 'भाई भंगी' व 'अछूत का भूत' नामक चर्चित कविताओं के रचयिता तिवारी जी जनपदीय पत्रकारिता के आधार स्तम्भ थे जिन पर लाल स्याही के अग्रलेख पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा सश्रम कारावास के साथ तीन वर्ष की सजा को झेलना पड़ा। तिवारी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों 'हलचल' व 'देहाती' ने तत्कालीन समय में जनपद की पत्रकारिता में नये कीर्तिमान कायम किये थे।

प्रथम विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की ओर से भर्ती अधिकारी के रूप में अपना सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन शुरू करने वाले बेनीमाधव जी स्वतन्त्रता प्राप्ति तक जनपदीय राजनीति के सर्वोच्च राजनेता के रूप में प्रसिद्ध रहे। अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में कांग्रेस से अलग हो अपने को किसान मजदूर पार्टी से जोड़कर समाजवादी अवधारणा पर आधारित समाज निर्माण की संकल्पना ली। आपके नाम पर ही वर्तमान समय में श्री बेनीमाधव तिवारी इण्टर कालेज, आटा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में बड़ी ही उपयोगी भूमिका अदा कर रहा है। जीवन के सभी पहलुओं का भरपूर आनन्द लेते हुए इस महामानव ने 1952 में अपनी अन्तिम सांस ली थी।

उग्रवादी आन्दोलन व जनपद में कांग्रेस के प्रादुर्भावकर्ता पं० मन्नीलाल पाण्डेय (1892–1939)

सन् 1892 में कालपी के केदारनाथ पाण्डेय के घर जन्में मन्नीलाल जी की प्रारम्भिक शिक्षा कालपी व उरई में माध्यमिक शिक्षा ग्वालियर व उच्चशिक्षा इलाहाबाद में सम्पन्न हुई। पाण्डेय जी जनपद-जालौन में कांग्रेसी आन्दोलन के जन्मदाता, समाजसेवा के अतिप्रिय पुरुष, तथा राजनीति में समूचे बुन्देलखण्ड में समकालीन नेताओं में सर्वाधिक वरिष्ठ माने जाते थे। आपने सन् 1916 में होम रूल आन्दोलन से जुड़कर अपनी देश भक्ति एवं स्वतन्त्रतावादी गतिविधियों का प्रारम्भ किया। पाण्डेय जी की पहली गिरफ्तारी दिसम्बर सन् 1921 में इलाहाबाद के आनन्द भवन में रौलट एक्ट का विरोध करने में हुई। आप ही जनपद के एकमात्र स्वतन्त्रता संग्रामी थे जिनको जेल में मोतीलाल नेहरू व जवाहरलाल नेहरू के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।⁽²³⁾

आप कांग्रेस की प्रान्तीय समिति के सदस्य सन् 1921 में बनाये गये तथा असहयोग आन्दोलन एवं नमक सत्याग्रह के समय गिरफ्तार किये जाने वाले जनपदीय लोगों के प्रमुख नेता थे। सन् 1924 में इन्हें जालौन जिला बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। आपने इस पद पर लगभग ढाई साल के शासन में अपनी नेतृत्व की अद्भुत क्षमता दिखाई।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू को जनपद लाने एवं उन्हें थैली भेंट करने में जनपदीय नेताओं में पाण्डेय जी की अग्रणी भूमिका रही। तिलक की सर्वेंट आल इंडिया सोसाइटी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, सेवासमिति, लोकमत पत्र का प्रकाशन, कालपी में सेवा समिति का गठन

की गतिविधियों में आप अजीवन सक्रिय रूप में जुटे रहे। सन् 1937 प्रान्तीय विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर रायसाहब कामता प्रसाद को पराजित कर अपनी कुशल चुनावी क्षमता का लोहा तत्कालीन नेताओं को मनवा दिया। पं० चतुर्भुज शर्मा के शब्दों में कहो तो “पाण्डेय जी बड़े मेधावी एवं स्वाभिमानी प्रकृति के पुरुष थे, उनकी भाषण क्षमता उच्च कोटि की थी, फौजदारी के चोटी के वकील थे, जिलाबोर्ड के जनता के प्रथम प्रतिनिधि अध्यक्ष के रूप में आपने जो शासन क्षमता दिखाई वह भी अद्भुत थी।” जनपद के अप्रितम पुरोधे कहे जाने वाले मन्नी लाल जी का लम्बी बीमारी के बाद असामयिक निधन दिसम्बर सन् 1939 में हो गया। आपके स्वर्गवासी होने से जनपदीय आन्दोलन व राजनीति में जो रिक्तता आयी उसमें लगा कि आन्दोलन थोड़े समय के लिए सुस्त हो गया था।⁽²⁴⁾

प्रारम्भिक स्वतन्त्रता आन्दोलन में जनपद-जालौन के योगदान का मूल्यांकन

जनपद के लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनपदीय जनता ने स्थानीय गतिविधियों से लेकर राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय स्तर के प्रत्येक आन्दोलन में उत्सुकता से हिस्सा लिया और बुन्देलखण्ड की स्वतन्त्रता की परम्परा को यथावत बनाए रखा। प्रारम्भिक स्वतन्त्रता आन्दोलन में जनपद के कोंच, कालपी, उरई तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों ने ब्रिटिश शासन का विरोध प्रतीकात्मक रूप से किया। वास्तव में सन् 1857 के विद्रोही की समाप्ति के बाद कुछ वर्षों तक जनपद जालौन में राष्ट्रवादी आन्दोलन की गतिविधियों की गति धीमी रही थी। इसका कारण यह था कि लोग तूफान के बाद की शान्ति की मनोदशा से गुजर रहे थे तथा

आगामी आन्दोलन हेतु शक्ति संचय कर रहे थे एवं भविष्य के कार्यक्रमों को निर्धारित करने हेतु योजनावद्ध तरीके से कार्य करने हेतु विचार विमर्श कर रहे थे। राष्ट्रीय क्षितिज पर जैसे ही अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसका जनपद के लोगों ने स्वागत किया। धीरे-धीरे कांग्रेस की बागडोर उग्रवादी नेताओं के हाथ में आयी और यह संस्था जनता, मजदूर एवं साधारण वर्ग के अधिक समीप आ गयी। जैसे ही कांग्रेसी आन्दोलन ने जन आन्दोलन का रूप धारण किया वैसे जनपद जालौन में इसमें अपनी भागीदारी विस्तृत आधार पर सुनिश्चित की।

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के समय क्रान्तिकारी गतिविधियों का केन्द्र रहा जनपद-जालौन संग्राम के पश्चात भी ठा0बरजोर सिंह, मीरकादिर अली आदि के रूप में अंग्रेजी शासन को अपनी छद्म नीति एवं देशभक्ति पूर्ण कार्यों से लगातार परेशानी पैदा करता था। इन वीर क्रान्तिकारियों के पश्चात जनपद में काफी समय तक क्रान्तिकारी गतिविधियों एक तरह से थम सी गयी। पुनः जनपद में देशभक्ति पूर्ण कार्यों की शुरुआत ब्रह्मानन्द के रूप में आर्यसमाजी गतिविधियों से प्रारम्भ हुई। इसी जनपद की भूमि में पं0केदारनाथ का राहुल सांकृत्यायन के रूप में नया नाम सृजित हुआ, जिन्होंने अपनी प्रारम्भिक कर्मभूमि इसी क्षेत्र को बनाया। जनपदीय जनता में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने का यह पहला कदम था। इस कदम से जनपद में कई पाठशालाओं की स्थापना हुई जिनसे जनपदीय जनता को शिक्षित करने में काफी योगदान दिया।

कांग्रेस की स्थापना से सम्पूर्ण देश में पुनःराष्ट्रीय चेतना की नई अलख जगी। लोगों को आपस में मिलजुल कर अपनी बातों को कहने का एक मंच रूप में कांग्रेस का प्रारम्भिक दौर गुजरा। कांग्रेस के उदारवादी युग इसकी गतिविधियाँ केवल प्रार्थना पत्रों को देने तथा नम्रतापूर्वक

अपनी माँगों को अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष प्रस्तुत करने तक सीमित रही। जनपद में इन गतिविधियों को प्रसारित का कार्य रायसाहब गोपालदास शर्मा द्वारा किया गया। शर्मा जी ने जनता को कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से परिचित कराते हुए उनमें सभा आदि करने का साहस पैदा किया। शर्मा जी ने अपने प्रारम्भिक प्रयासों से ही जनता में लोकप्रियता पा ली एवं समस्त जनता के अन्दर स्वतन्त्रता आन्दोलन के बीज बो दिये। इस प्रकार उदारवादी युग में जनपद में स्वतन्त्रता आन्दोलन एक अन्धे युग की भाँति गुजरा।

उग्रवादी युग के दौरान जनपद में स्वतन्त्रता आन्दोलन की गतिविधियों को गति प्राप्त हुई। इस दौर में ऐनी बेंसेट व तिलक की उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित हो मन्नीलाल एवं बेनीमाधव तिवारी द्वारा विधिवत् कांग्रेस की सदस्यता ली गयी। इस समय में कांग्रेसी नेताओं ने जनपदीय जनता को कांग्रेस से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये गये। जिसमें उन्होंने काफी सफलता प्राप्त करते हुए जनपद के प्रमुख नगरों कालपी, उरई, कोंच, जालौन आदि में क्रान्तिकारी कांग्रेसी नेताओं के युवावस्था का था परन्तु इस समय जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्र आन्दोलन की गतिविधियों से जुड़ चुका था। इस उग्रवादी युग में जनपद में न तो कोई गिरफ्तारी हुई और न कोई ब्रिटिश शासन के कोप भांजन का शिकार हुआ, परन्तु जनपदीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असन्तोष अन्दर ही अन्दर भड़क रहा था।

सन्दर्भ सूची

1. Masani R.P. : Dada Bhai Nauraji, P. 427
2. Cottan Sir Henry : New India, P-28

3. Chinta Mani : Indian Politics since the mutiny, P.-39
4. उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अभिलेखागार के लोकार्पण स्तम्भ में उल्लेखित।
5. A.C. Mazumdar : Indian National Evolution, P-22
6. A.C. Mazumdar : Indian National Evolution, P-24
7. मजूमदार आर०सी० : भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ-208
8. Annie Beasant : How India Fought Freedom, P.-465
9. Navinson : The New Spirit in India, P -226
10. नायर, एम०पी० श्रीकुमारन का लेख, जनरल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री।
11. काटन, इण्डिया एण्ड होम मेमोरीज, पृष्ठ-316।
12. व्यक्तिगत साक्षात्कार : ब्रजेश कुमार पालीवाल, दिनांक – 26.10.2007
13. व्यक्तिगत साक्षात्कार : नम्रता तिवारी, दिनांक : 27.02.2011
14. Annie Beasant : India, Bound or Free, P- 162, 163
15. Annie Beasant : How India Fought for freedom, P-566,567
16. Nehru J.L. : Autobiography, P.-53,55
17. सिंह गुरुमुख निहाल : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास, पृष्ठ-246
18. Banerjee S.N. : A Nation in the Making, P-303
19. शर्मा चतुर्भुज : विद्रोही की आत्म कथा, चतुर्भुज प्रकाशन 33, पानदरीबा, लखनऊ संस्करण द्वितीय (2005), पृष्ठ-23
20. Singh Balwant : Jalaun Gazetteers, 1989, P.-50
21. सिंह बलवन्त : जालौन गजेटियर, 1989, पृष्ठ – 50
22. व्यक्तिगत साक्षात्कार : नम्रता तिवारी, दिनांक 27.02.2011
23. दैनिक जागरण, कानपुर, 9 अगस्त 2008, पृष्ठ नं० 6
24. व्यक्तिगत साक्षात्कार : अविनाश पाण्डेय (मन्नीलाल पाण्डेय के दत्तक पुत्र), दिनांक-10.09.2008